बजट में पूंजीगत व्यय का बढ़ना उत्साहवर्धक

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ की नई सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया। नवंबर 2000 में अस्तित्व में आने वाले छत्तीसगढ़ ने पिछले दो दशकों में तेजी से प्रगति की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह 10 वां सबसे बड़ा प्रदेश एक ओर जहां प्रचुर प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है, वहीं दूसरी ओर कृषि और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था ने इसे पर्याप्त भौतिक समृद्धि भी प्रदान की है और आज भी प्रगति की अपार संभावनाएं यहां विद्यमान हैं। 8 फरवरी को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण का सार भी यही था। कोई बजट कितना प्रभावशाली होगा, इसका प्रमुख निर्धारक तत्व होता है, पूंजीगत व्यय।

प्रो. संजीव प्राशर, आइआइएम, रायपुर

किसान : कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी मूल्य भी शामिल है। चूंकि प्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती से जुड़ा है, तो ये प्रावधान अर्थव्यवथा के लिए लाभकारी होंगे।

महिला : महतारी वंदन योजना को बजट में शामिल करने तथा इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने से महिलाओं को काफी सहारा होगा, जो उनकी उत्पादकता को और अंततः अर्थव्यवस्था को भी परोक्ष रूप से बूस्ट करने में सहायक होगा।

लोकस्वास्थ्य : सरकार ने लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट को दोगुना कर दिया है। इसके अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति के महत्वाकांक्षी जल-जीवन मिशन के लिए 4, 000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वीकृत 1,820 करोड़ रुपये मील का पत्थर साबित होंगे।

शिक्षा : आइआइटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल मानी जा सकती है। 160 आइटीआइ के उन्नयन रोजगार के नए स्रोत उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के मद में दो हजार करोड़ की वृद्धि क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

Naidunia, 10th Feb. 2024, P. 2